

नवाभारत



5 1300 स्टेशनों का पुनर्निर्माण जारी



6 विमान यात्रियों के हित में नया कानून आवश्यक



7 रेपो कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहुंचे



8 हिटमैन शीर्ष पर बरकरार

कांग्रेस पुश्तैनी वोट चोर : शाह

- ▶ अमित शाह बोले- हारने पर ठिकरा ईसी पर फोड़ते हैं
- ▶ कांग्रेस ने सदन से किया वॉकआउट

नई दिल्ली, 10 दिसंबर. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा का जवाब दिया. उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि चुनाव सुधार पर चर्चा से बीजेपी के लोग भागते नहीं हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पुश्तैनी वोट चोर है.

इस पर शाह ने कहा कि मैं 30 साल से विधानसभा और लोकसभा से चुनकर आ रहा हूँ. मुझे संसदीय प्रणाली का लंबा अनुभव है. विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का जवाब आप दीजिए. मैं सुनाना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से संसद नहीं चलेगी. मेरे बोलने का क्रम मैं तय मैं करूँगा. इस तरीके से संसद नहीं चलेगी. शाह ने कहा कि हमने कभी चुनाव आयोग पर आरोप नहीं लगाए. कांग्रेस एक नया पैटर्न फैला रही है. ममता, स्टालिन, राहुल गांधी ने ईसी पर आरोप लगाए.



मतदाता सूची में सुधार की जिम्मेदारी आयोग की

मतदाता सूची बनाने और सुधार करने की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की है. अब 325 जो अनुच्छेद है किसी भी पात्र मतदाता को सूची से बाहर नहीं रखा जा सकता. मतदाता होने की शर्तें 326 में निहित हैं. पहली शर्त है मतदाता भारत का नागरिक होनी चाहिए. दूसरा 18 साल से ऊपर उम्र होनी चाहिए. ये सभी पात्रता चुनाव आयोग को देखनी है, कानून बनाने की सिफारिश करने की शक्ति चुनाव आयोग को दी है. ये कह रहे थे कि इनको एसआईआर का अधिकार नहीं है, संविधान पूर्ण अधिकार देता है.



चर्चा के लिए शाह को चैलेंज

इस पर सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपनी सीट से खड़े हुए और शाह से कहा कि मैं आपको चैलेंज करता हूँ. आप मेरी वोट चोरी की तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चर्चा करें. राहुल ने कहा कि गृहमंत्री शाह का रियासत पूरी तरह से घबराया हुआ और डरा हुआ रियासत है. इस दौरान सदन में 7 से ज्यादा बार हंगामा हुआ. आखिर में कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया.

शाह के तीखे प्रहार

- इंदिरा गांधी की चुनाव में जीत वोट चोरी थी. इस पर इलाहबाद हाईकोर्ट ने उठाए थे सवाल
- सोनिया नागरिक बनने से पहले वोटर बनी थीं
- देश में नया पैटर्न चल रहा है. हारने पर चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं.
- चुनाव में हारने पर ईसी को करते हैं बदनाम
- पटेल को ज्यादा वोट मिले और फिर भी नेहरू पीएम बने

- कोई पत्रकार बीजेपी का एजेंट नहीं
- घुसपैठियों को देश से बाहर करने की बात पर विपक्ष सदन से बाहर क्यों भागा
- एसआईआर का निर्णय हमारा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का है
- घुसपैठिए तय नहीं करेंगे सीएम और पीएम
- चुन-चुनकर विदेशी बाहर भेजे जायेंगे
- मतदाता सूची नई हो या पुरानी आपका (विपक्ष) का हारना तय है

एक नजर में

तिरुपति मंदिर में करोड़ों का घोटाला उजागर!

तिरुपति. प्रसिद्ध तिरुमला तिरुपति श्री वेङ्कटेश्वर मंदिर में प्रसिद्ध लड्डू घोटाले के बाद अब दुपट्टा घोटाला सामने आया है. देवस्थानम में सिल्क बताकर घटिया पॉलिएस्टर दुपट्टे सप्लाई करने का मामला उजागर हुआ है. पिछले 10 वर्षों में कॉन्ट्रैक्टर ने टीटीडी को करोड़ों का चूना लगाया. आंध्र सरकार ने मामले को एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंप दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक, कॉन्ट्रैक्टर ने शुद्ध मुलबेरी सिल्क दुपट्टों के नाम पर 100 प्रतिशत पॉलिएस्टर के दुपट्टे टीटीडी को बेचे. एक दुपट्टे की बाजार कीमत मात्र 350 रुपये होने के बावजूद इसे 1300 रुपये में बिल किया गया. ये दुपट्टे मंदिर में दानकर्ताओं को प्रसाद के रूप में दिए जाते हैं. और वेदाशीर्वाचनम् जैसे पवित्र अनुष्ठानों में भगवान को चढ़ाए जाते हैं.

12 हिस्सों में बंट सकता है पाकिस्तान

लाहौर, 10 दिसंबर. पाकिस्तान के चारों प्रांतों को 12 हिस्सों में बांटने की तैयारी चल रही है. देश के संचार मंत्री अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि देश में छोटे-छोटे प्रांत बनाना अब तय है. उनका कहना है कि इससे शासन बेहतर होगा और जनता को सेवाएं आसानी से मिलेंगी. अब्दुल अलीम खान रविवार को शेखपुरा में इस्तेहकाम-ए-पाकिस्तान पार्टी के कार्यक्रमों सम्मेलन में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने कहा कि सिंध और पंजाब में तीन-तीन नए प्रांत बनाए जा सकते हैं. ऐसा ही विभाजन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी हो सकता है. खान ने कहा कि हमारे आस-पास के देशों में कई छोटे प्रांत हैं. इसलिए पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए.

गुस्ताखी माफ



सुप्रीम कोर्ट को बदनाम न करें : पूर्व जज

- ▶ सीजेआई के सपोर्ट में उतरे 44 पूर्व न्यायाधीश
- ▶ रोहिण्या घुसपैठिया विवाद में नया मोड़

नई दिल्ली, 10 दिसंबर. सुप्रीम कोर्ट ने दो दिसंबर को रोहिण्या शरणार्थियों पर सुनवाई के दौरान बड़ी टिप्पणी की थी. चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि क्या भारत सरकार ने रोहिण्याओं को शरणार्थी घोषित किया है? अगर कानूनी तौर पर ये शरणार्थी नहीं हैं तो ये फिर घुसपैठिए हैं.

घुसपैठियों के लिए रेड कार्पेट नहीं बिछाया जा सकता है.



रोहिण्या कानून के तहत भारत नहीं आए थे

पूर्व जजों ने कहा कि रोहिण्या भारतीय कानून के तहत शरणार्थी के रूप में भारत नहीं आए थे. उन्हें किसी भी वैधानिक शरणार्थी-सुरक्षा दावे के तहत प्रवेश नहीं दिया गया था. ज्यादातर मामलों में उनकी एंटी अवैध है.

सीजेआई की इसी टिप्पणी के बाद विवाद छिड़ गया. घुसपैठिए समर्थित कई वरिष्ठ पूर्व जजों और वकीलों ने उनके इस बयान पर आपत्ति जताई. उन्होंने चीफ जस्टिस को ओपन लेटर लिखा और नाराजगी जाहिर की. उन्होंने कहा कि ये भाषा बहुत आपत्तिजनक है. इसके बाद सीजेआई को निशाना बनाया और उनके खिलाफ अभियान चलाया गया. इस पर अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 44 जजों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है. ये सभी जज सीजेआई के सपोर्ट में खड़े हुए हैं. सभी ने एक सुर में कहा कि सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करने की कोशिश हो रही है.

‘रतन टाटा सम्मान’ मुंबई में लॉन्च



▶ नारायण मूर्ति सहित तीन भारतीय दिग्गजों को दिया अवॉर्ड

मुंबई, 10 दिसंबर. साउदन कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने पहला यूएससी-रतन टाटा पुरस्कार प्रदान किया. यह सम्मान इंफोसिस के संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति को तकनीक, व्यवसाय, इंजीनियरिंग और परिवर्तनकारी नेतृत्व में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया. समारोह में दो अन्य उद्योग जगत

एयर सिक्वोरिटी को मिलेगा स्वदेशी कवच

नई दिल्ली, 10 दिसंबर. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) को मिसाइलों, ड्रोन और तेज रफ्तार वाले विमानों जैसे दुश्मन के हवाई खतरों से बचाने के लिए स्वदेशी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने की तैयारी की जा रही है.

वरिष्ठ रक्षा सूत्रों ने बताया कि एनसीआर की सुरक्षा के लिए मल्टीलेयर इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम (आइएडीडब्ल्यूएस) स्वदेशी एयर डिफेंस मिसाइलों जैसे क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल (क्यूआरएसएम) सिस्टम और वेरी शार्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के साथ तैनात होगा. आइएडीडब्ल्यूएस पर

5-40 हजार रुपए तक बढ़ाने की अनुमति कैसे मिली

इंडिगो संकट | दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को फटकारते हुए पूछा

नई दिल्ली, 10 दिसंबर. दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 दिसंबर को इंडिगो संकट पर केंद्र सरकार को कड़ी चेतावनी दी। कोर्ट ने सवाल उठाया कि सरकार ने स्थिति बिगड़ने से पहले कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया और अन्य एयरलाइंस को किराया 5 हजार से 40 हजार रुपए तक बढ़ाने की अनुमति कैसे मिल गई। कोर्ट ने कहा कि ऐसा संकट देश की अर्थव्यवस्था और यात्रियों की सुविधा-दोनों को नुकसान पहुंचाता है।

इंडिगो को डीजीसीए नियमों के मुताबिक सभी प्रभावित



यात्रियों को मुआवजा और जरूरत पड़ने पर नुकसान की भरपाई करनी होगी। केंद्र को कानून के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई करने का आदेश-लाइसेंस निलंबन, रद्दीकरण और 1 करोड़ तक जुर्माने समय क्रियान्वित कर रहा है, जब सवाल-हाईकोर्ट ने पूछा कि अन्य

एयरलाइंस को किराया इतनी बड़ी मात्रा में बढ़ाने की अनुमति कैसे दी गई। डीजीसीए भी जांच के दायरे में-मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा-जांच सिर्फ इंडिगो की नहीं, डीजीसीए के कामकाज की भी होगी। पर्याप्त स्टाफ और पायलट की भर्ती का निर्देश, यात्रियों को दोबारा परेशानी नहीं होनी चाहिए। इंडिगो संकट के बीच अन्य एयरलाइंस ने भी अपने परिचालन में तेज बदलाव किए हैं। एयर इंडिया ग्रुप ने अपनी उड़ानें 3 प्रतिशत घटा दी हैं जबकि अकासा एयर ने 5.7 प्रतिशत प्लाइंट कम कर दी हैं।

आठ सदस्यीय विशेष निगरानी दल नियुक्त

इंडिगो संकट के बीच नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयरलाइन के परिचालन पर कड़ी निगरानी रखने के लिए एक आठ सदस्यीय विशेष निगरानी दल नियुक्त किया है। इस टीम के दो अधिकारी प्रतिदिन इंडिगो के कॉर्पोरेट मुख्यालय में भौतिक रूप से मौजूद रहेंगे और उड़ान संचालन, रोस्टरिंग, वरू उपलब्धता, शेड्यूलिंग तथा संकट प्रबंधन से जुड़े कई महत्वपूर्ण परिचालन मापदंडों की समीक्षा करेंगे।

एमपी सरकार अपने खर्च पर बनाएगी हाई-स्पीड कॉरिडोर

- ▶ सिंहस्थ के लिये 52 बड़े कामों पर 12 हजार करोड़ खर्च होंगे
- ▶ तीन वर्ष की कार्ययोजना को लेकर दिये प्रजेंटेशन में दी गई जानकारी



प्रशासनिक संवाददाता भोपाल, 10 दिसंबर. मप्र सरकार अब अपने खर्च पर हाई-स्पीड कॉरिडोर बनाएगी, इनमें उज्जैन-इंदौर और भोपाल पूर्वी बायपास जैसे बड़े कॉरिडोर भी शामिल हैं. इतना ही नहीं उज्जैन सिंहस्थ के लिये 52 बड़े कामों को हाथ में लिया जाएगा, जिस पर 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च होगी.

यह जानकारी बुधवार को लोक निर्माण विभाग की तीन वर्ष की कार्ययोजना को लेकर दिये गए प्रजेंटेशन में दी गई. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में विभाग की दो वर्ष की उपलब्धियों और अगले तीन वर्ष की कार्ययोजना को लेकर समीक्षा बैठक की. इस दौरान बताया गया कि प्रदेश में 6-लेन एवं 4-लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का व्यापक नेटवर्क विकसित कर औद्योगिक क्षेत्रों,

कृषि मंडियों, लॉजिस्टिक जोन्स और प्रमुख शहरों को तेज गति से जोड़ा जाएगा. इसी तरह एनएचएआई के सहयोग से सतना-चित्रकूट, रीवा-सीधी, बैतुल-खंडवा-इंदौर, जबलपुर-झालमलवाड़ जैसे राष्ट्रीय महत्व के हाईवे का विस्तार किया जाएगा. वहीं अगले तीन वर्षों में 600 नए लोक कल्याण सरोवर का निर्माण कर सड़क निर्माण से उत्पन्न मिट्टी का वैज्ञानिक उपयोग और जल-संरक्षण को एकीकृत मांडल के रूप में लागू किया जाएगा. विभागीय भवनों में 100 फीसदी सौर ऊर्जा अपनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे ऊर्जा लागत में भारी कमी और हरित भवन अवधारणा को बढ़ावा मिलेगा.

सिंहस्थ के काम जून 2027 तक पूरा करें

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि एक्सप्रेस-वे आधुनिक समय की मांग है. इन अधोसंरचनाओं के विकास में ग्रामीण क्षेत्र की सुविधाओं का ध्यान रखा जाये. आवश्यकतानुसार फ्लाई-ओवर, अंडर-पास, सर्विस लेन की प्रस्ताव में शामिल करें. बैठक में बताया गया कि सिंहस्थ-2028 के कार्य प्राथमिकता से किए जा रहे हैं. प्रस्तावित कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है. दिसम्बर माह के अंत तक कार्य प्रारंभ हो जायेंगे. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए कार्यों को जून-2027 तक पूर्ण किया जाये.